गहन विश्लेषण: हाल के समय में एनबीएफसी क्षेत्र की समीक्षा

अभ्युदय हर्ष, रजनीश कुमार चंद्रा, नंदिनी जयकुमार और ब्रिजेश पी. द्वारा ^

वैश्विक स्तर पर, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) पिछले कुछ वर्षों में आकार और जटिलता में बढ़े हैं, जिससे वे वित्तीय प्रणाली में अन्य संस्थाओं के साथ जुड़ गए हैं। भारत में भी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) वित्तीय प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गई हैं, जो एनबीएफसी के ऋण से जीडीपी अनुपात में क्रमिक वृद्धि में परिलक्षित होती है। इस क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के साथ-साथ बढ़ती अंतर्संबंधता और एनबीएफसी के बदलते जोखिम प्रोफाइल को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2022 में स्केल-आधारित विनियमन (एसबीआर) की शुरुआत की। इस बदलाव के बीच, एनबीएफसी क्षेत्र सुदृढ़ बना हुआ है, जिसमें ऋण, पर्याप्त पूंजी और कम चूक अनुपात में लगातार दोहरे अंकों की वृद्धि हो रही है।

परिचय

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान[1] (एनबीएफआई) वैश्विक वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं, जो वर्तमान में वैश्विक वित्तीय आस्तियों का लगभग आधा हिस्सा हैं। एनबीएफआई क्षेत्र की विशेषताएं विभिन्न क्षेत्राधिकारों में भिन्न होती हैं। तेजी से विविध और जटिल गतिविधियों के साथ, एनबीएफआई वित्तीय और वास्तविक अर्थव्यवस्था (एफएसबी, 2023ए) के अन्य क्षेत्रों के साथ गहराई से जुड़ रहे हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पर्यवेक्षित संस्थाओं पर लागू विभिन्न नीतियां एक प्रणाली-व्यापी परिप्रेक्ष्य से एक साथ फिट हों।

किसी भी विविध वित्तीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक अलग-अलग जोखिम प्रोफाइल वाले विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थानों की उपस्थिति है, जो विभेदित नियामकीय समाधान के लिए आवश्यक होती है। इस उद्देश्य के लिए, अक्टूबर 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों[2] (एनबीएफसी) के लिए स्केल -आधारित विनियमन (एसबीआर) लागू किया गया, जो एनबीएफसी के आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर विभेदक नियामक आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। यह प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन के व्यापक लक्ष्य का त्याग किए बिना, गतिविधि-आधारित और इकाई-आधारित विनियमन की सर्वोत्तम विशेषताओं को जोड़ता है। भारत में, एनबीएफसी वित्तीय प्रणाली के एक अभिन्न अंग बन गए हैं, जो एनबीएफसी के ऋण से जीडीपी अनुपात और एनबीएफसी के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण जैसे मेट्रिक्स में क्रमिक वृद्धि से परिलक्षित होता है।

यह लेख हाल के समय में एनबीएफसी क्षेत्र के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। लेख का शेष भाग निम्नलिखित खंडों में विभाजित है। खंड II एनबीएफसी क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें भारत पर विशेष ध्यान दिया गया है। खंड III भारत में एनबीएफसी क्षेत्र के विनियामकीय विकास का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमें बैंकों और एनबीएफसी तथा एनबीएफसी के बीच विद्यमान विनियामकीय विभेदों पर प्रकाश डाला गया है। खंड IV तुलन पत्र की गतिशीलता, साथ ही एनबीएफसी के ऋण के क्षेत्रीय वितरण, लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता का विश्लेषण करता है। लेख का अंतिम खंड उभरती चुनौतियों पर कुछ टिप्पणियों के साथ समाप्त होता है।

II. भारत में एनबीएफआई: एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य

एनबीएफआई वैश्विक वित्तीय प्रणाली में ऐसी सेवाएँ प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो ज़रूरी नहीं कि बैंक ही प्रदान करें। वे ऋण तक पहुँच बढ़ाने और आर्थिक विकास को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय के साथ, एनबीएफआई

^ लेखक आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग से हैं। यह आलेख श्री गोपीनाथ प्रहलाद चार तुलसी, परामर्शदाता के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

[1] वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) एनबीएफआई क्षेत्र को सभी गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं के एक व्यापक माप के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें वे सभी वित्तीय संस्थान शामिल हैं जो केंद्रीय बैंक, बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान नहीं हैं।

[2] भारत में एनबीएफसी व्यापक एनबीएफआई क्षेत्र का एक उपसमूह हैं और इस आलेख में एनबीएफसी से तात्पर्य आरबीआई द्वारा विनियमित गैर-बैंकों से है, जैसा कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत परिभाषित किया गया है।

का आकार और जटिलता बढ़ी है, जिसने उन्हें वित्तीय प्रणाली में अन्य संस्थाओं के साथ जोड़ दिया है। निहितार्थ से, एनबीएफआई क्षेत्र में दबाव वित्तीय प्रणाली के अन्य प्रतिभागियों को अधिक तेज़ी से और व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है। इस हद तक वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने एनबीएफआई के लिए नवाचारों को ट्रैक करने और प्रणालीगत और उभरते जोखिमों की पहचान करने के लिए एक वार्षिक प्रणाली-व्यापी निगरानी ढांचा बनाया (एफएसबी, 2023बी)।

वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद से, एनबीएफआई का आकार बढ़ गया है और अब वे वैश्विक वित्तीय प्रणाली (चार्ट 1 ए) का सबसे बड़ा घटक बन गए हैं। संस्थानों का यह पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही विविध है और व्यापार मॉडल तथा क्षेत्राधिकार के आधार पर अलग-अलग है। जीएफसी के बाद, पहली बार, 2022 में वैश्विक स्तर पर एनबीएफआई आस्तियों में 5 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। यह मुख्य रूप से उच्च ब्याज दरों और कठोर चलनिधि तथा वित्तीय स्थितियों के प्रभाव के कारण था, जिसे मुद्रास्फीति के दबाव के कारण 2022 में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं ने अनुभव किया (एफएसबी, 2023 बी)।

भारत में, वित्तीय प्रणाली बैंक-प्रधान बनी हुई है। एनबीएफआई क्षेत्र की आस्तियों के आकार के मामले में बैंकिंग क्षेत्र से पीछे है, हालांकि, समय के साथ उनके बीच का अंतर कम

सारणी 1: भारतीय वित्तीय प्रणाली में प्रमुख प्रतिभागी

(मार्च 2023 के अंत में)

		कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में
1.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक*	53.7
2.	सहकारी बैंक#	4.7
3.	एनबीएफआई	41.6
	*3.1. एनबीएफसी^*	*15.2*
	*3.2. एआईएफआई^^*	*3.2*
	3.3. बीमा कम्पनियां	*12.8*
	3.4. पेंशन निधि	*1.9*
	3.5. म्यूचुअल फंड	*8.4*
कुल		**100.0**

नोट: * आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को संदर्भित करता है।
शहरी और ग्रामीण ऋण सहकारी समितियाँ शामिल हैं। उत्तरार्द्ध के लिए डेटा मार्च 2022 के अंत से संबंधित हैं।
^ इसमें आरबीआई के साथ पंजीकृत सभी एनबीएफसी और एआरसी शामिल हैं; और एनएचबी के साथ पंजीकृत सभी एचएफसी शामिल हैं।
^ ^ पांच अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को संदर्भित करता है, अर्थात् नाबार्ड, एक्जिम बैंक, सिडबी, एनएचबी और एनएबीएफआईडी।

स्रोत: आरबीआई, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए।

हो रहा है (चार्ट 1बी और सारणी 1)। उनका प्रणालीगत महत्व बढ़ रहा है, जैसा कि जीडीपी के हिस्से के रूप में एनबीएफआई के आकार में संकेत दिया गया है। 2022 में, भारत में एनबीएफआई ने वैश्विक स्तर पर संकुचन के विपरीत लगभग 12 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की (चार्ट 2)। घरेलू एनबीएफसी क्षेत्र के निवेश कोष में संकुचन की भरपाई उधार देने वाली कंपनियों के आकार में विस्तार से अधिक हुई, जो नैरो मेजर में कुल एनबीएफआई आस्तियों का 79 प्रतिशत हिस्सा है (सारणी 2)।

चार्ट 1: कुल वित्तीय आस्तियां

(दिसंबर के अंत में)

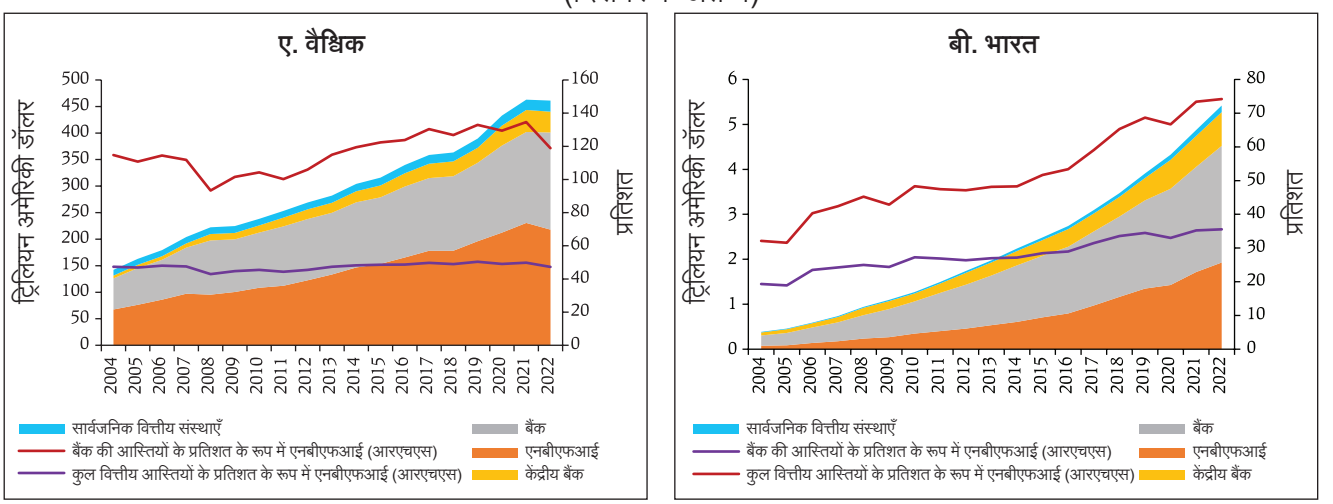

नोट: वैश्विक में भारत भी शामिल है।
स्रोत: गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट, 2023.

चार्ट 2: भारत में एनबीएफआई के घटक और विकास

(दिसंबर के अंत में)

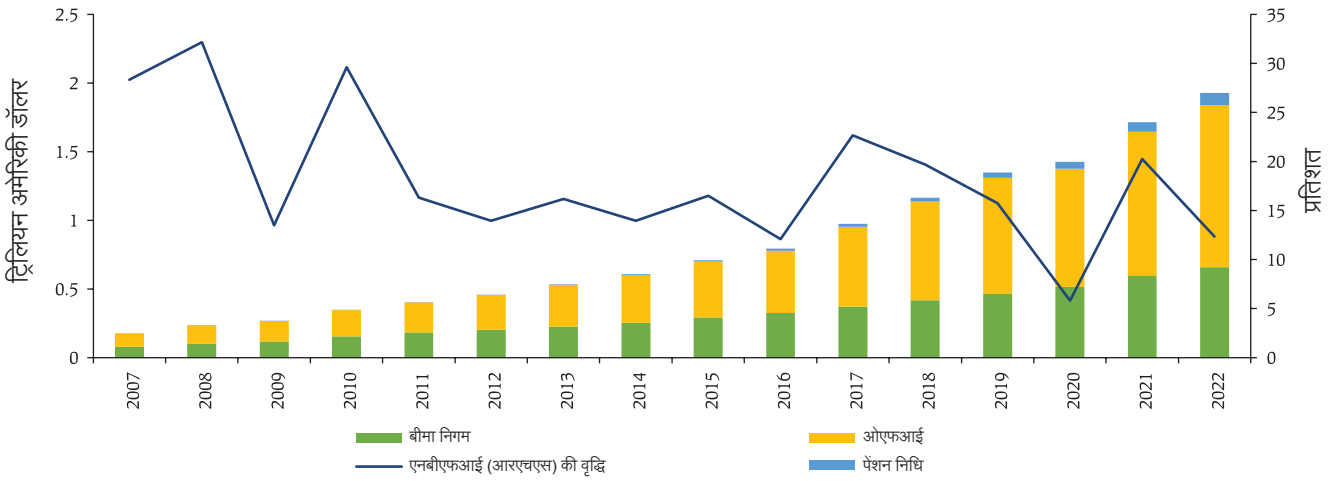

नोट: अन्य वित्तीय मध्यस्थ (ओपीआई) एनबीएफआई क्षेत्र के एक उप समूह को संदर्भित करते हैं, जिसमें वे सभी वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं जो केंद्रीय बैंक, बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, बीमा निगम, पेंशन निधि संस्था या वित्तीय सहायक संस्था नहीं हैं।

स्रोत: गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट, 2023.

एनबीएफआई द्वारा अपने अंतर्संबंधों के कारण उत्पन्न बैंक जैसी वित्तीय स्थिरता जोखिमों की सीमा का आकलन करने के लिए, एफएसबी ने एक 'नैरो मेजर' तैयार किया, जो एनबीएफआई गतिविधियों के एक उपसमूह पर केंद्रित है। यह मेजर एनबीएफआई को पांच आर्थिक कार्यों (ईएफ) या गतिविधियों में विभाजित करता है (सारणी 2)। दिसंबर 2022 के अंत में, वैश्विक नैरो मेजर आस्तियों में उनके हिस्से के अनुसार सबसे बड़े क्षेत्राधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका (30.4 प्रतिशत), आठ प्रतिभागी यूरो क्षेत्र क्षेत्राधिकार (21.5 प्रतिशत), चीन (16.3 प्रतिशत) और केमैन द्वीप (12.8 प्रतिशत) थे। वैश्विक नैरो मेजर में 2022 में गिरावट आई, जो लगभग पूरी तरह से ईएफ1 में गिरावट के कारण हुई, जबकि अन्य चार ईएफ में वृद्धि जारी रही। भारत में, नैरो मेजर में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो लगभग पूरी तरह से ईएफ2 के कारण हुई, जबकि ईएफ1 में गिरावट दर्ज की गई।

सारणी 2: इकाई के प्रकार और गतिविधियों के अनुसार नैरो मेजर संरचना

(दिसंबर 2022 के अंत में)

आर्थिक कार्य / गतिविधि	निकाय प्रकार	नैरो मेजर में आर्थिक कार्यवार हिस्सेदारी (प्रतिशत में)			
		एई	ईएमई	वैश्विक	भारत
ईएफ1	मनी मार्केट फंड, फिक्स्ड इनकम फंड, मिक्स्ड फंड, क्रेडिट हेज फंड, रियल एस्टेट फंड	72.6	81.0	74.3	20.1
ईएफ2	वित्त कंपनियां, लीजिंग/फैक्टरिंग कंपनियां, उपभोक्ता ऋण कंपनियां	7.7	9.0	7.9	79.0
ईएफ3	ब्रोकर-डीलर, कस्टोडियल खाते, प्रतिभूति वित्त कंपनियां	7.3	6.5	7.1	0.4
ईएफ4	क्रेडिट बीमा कंपनियां, वित्तीय गारंटर, मोनोलाइन बीमाकर्ता	0.3	0.1	0.2	0.0
ईएफ5	प्रतिभूतिकरण साधन, संरचित वित्त साधन, आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ	9.1	3.1	7.8	0.4
गैर-आवंटित	अन्य वित्तीय सहायक जिन्हें एनबीएफआई से बैंक जैसी वित्तीय स्थिरता जोखिमों में शामिल माना जाता है, लेकिन जिन्हें किसी विशिष्ट आर्थिक कार्य प्रदान नहीं किए जा सकते हैं।	3.2	0.3	2.6	-
कुल		100.0	100.0	100.0	100.0
कुल एनबीएफआई क्षेत्र के हिस्से के रूप में नैरो मेजर		26.1	49.2	28.9	42.2

टिप्पणियाँ: 1. 29 अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 85 प्रतिशत का योगदान करते हैं और जिनके लिए अधिक विस्तृत डेटा उपलब्ध था।
2. सूचीबद्ध संस्थाएँ संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन विशिष्ट उदाहरण दर्शाती हैं।

स्रोत: गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता पर वैश्विक निगरानी रिपोर्ट, 2023।

वैश्विक स्तर पर, अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के साथ-साथ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में, ईएफ1 सबसे बड़ा घटक है। दूसरी ओर, भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों में, ईएफ2, जिसमें अल्पकालिक वित्तपोषण पर निर्भर ऋण देने वाली संस्थाएँ शामिल हैं, सबसे बड़ा घटक है। ईएफ2 में वित्त कंपनियों का वर्चस्व है, जो उपभोक्ता वित्त, ऑटो वित्त, खुदरा बंधक प्रावधान, वाणिज्यिक संपत्ति वित्त और उपकरण वित्त जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बाद भारत में वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी ईएफ2 आस्ति थी।

ईएफ2 में संस्थाएं विशेष ध्यान देने योग्य हैं क्योंकि वे परिपक्वता परिवर्तन में शामिल हैं और बैंकिंग क्षेत्र के साथ उनका अधिक अंतर्संबंध हो सकता है। बैंकों की तरह, ऋण मध्यस्थता के साथ, इनमें से कुछ संस्थाएं सार्वजनिक जमा और/या खुदरा वित्त पोषण के अन्य रूपों को भी स्वीकार कर सकती हैं, जो दबाव की अवधि के दौरान प्रणालीगत जोखिम को बढ़ा सकती हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफआई के संचालन वाले क्षेत्राधिकारों में नियामक, आमतौर पर एनबीएफआई को चालू खाते/मांग जमा की पेशकश करने से प्रतिबंधित करके इन संस्थाओं को बैंकों से अलग करते हैं। इसके अलावा, ये संस्थाएं सामान्य रूप से अन्य एनबीएफआई उधारदाताओं की तुलना में अधिक कठोर अपेक्षाओं के अधीन रखे जाते हैं (एहरेनट्राड, म्यूर, नोबल, और ज़मिल, 2024)। भारत में जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफआई के पास जमा बीमा कवरेज नहीं है क्योंकि जमा बीमा के अंतर्गत केवल बैंकों की जमाराशि ही आती है। लगभग सभी क्षेत्राधिकारों में इन संस्थाओं को मांग जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती है (चार्ट 3)। इस प्रकार, बैंक विनियमन के विपरीत, जिसके लिए वैश्विक विवेकपूर्ण मानक हैं, एनबीएफआई विनियमन के लिए ऐसा कोई ढांचा मौजूद नहीं है।

III. भारत में एनबीएफसी क्षेत्र का विनियामकीय विकास

1964 से, एनबीएफसी को आरबीआई अधिनियम, 1934 (आरबीआई, 2021बी) के अध्याय III बी के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के क्रम में, रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर एनबीएफसी पर लागू विनियमों को अद्यतन किया है, जो नियम-आधारित से सिद्धांत-आधारित विनियामकीय दृष्टिकोण में परिवर्तित हो रहा है। 1998 में, एनबीएफसी को सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, इसके बाद 2006 में ₹100 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) की शुरुआत की गई। 2014 में, एनबीएफसी के लिए विनियामकीय

चार्ट 3: जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफआई की विशेषताएं

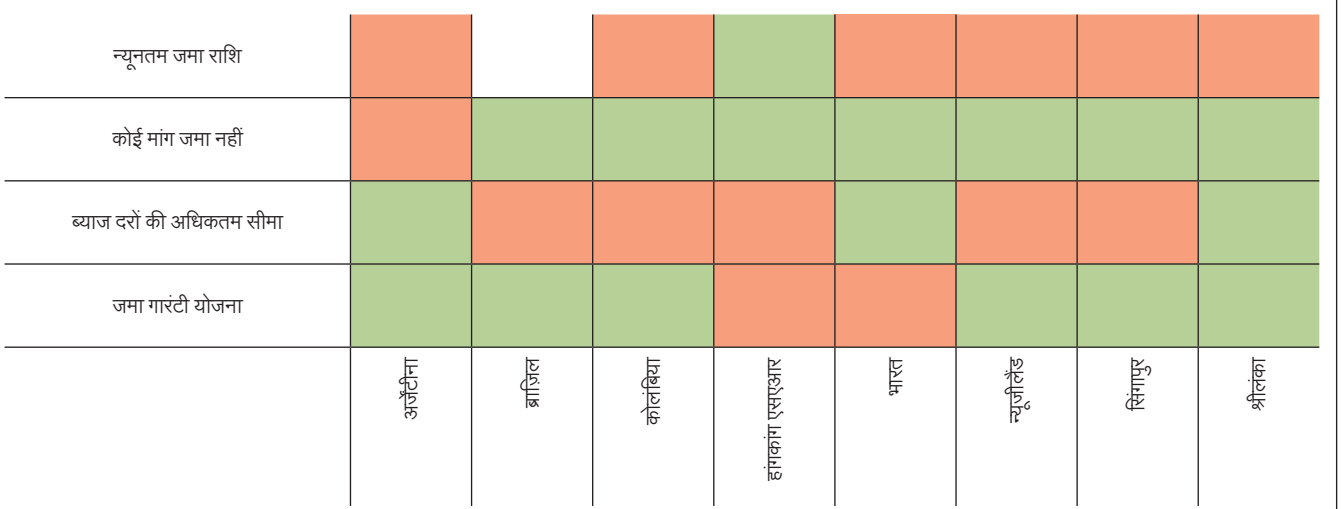

नोट: हरा लागू; लाल = लागू नहीं; और रिक्त = उपलब्ध नहीं।
स्रोत: एहरेनट्राड, म्यूर, नोबल, और ज़मिल, 2024; श्रीलंका केंद्रीय बैंक।

ढांचे की समीक्षा की गई और इस क्षेत्र को गतिविधि आधारित विनियमन में परिवर्तित कर दिया गया। विशेषज्ञ समितियों[3] की सिफारिशों से संकेत लेते हुए नए नियम बनाए गए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण की सीमा को ₹100 से बढ़ाकर ₹500 करोड़ कर दिया गया, आस्ति वित्त कंपनियों के लिए मौजूदा जमा को नवीनीकृत करने या नए सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने के लिए निवेश ग्रेड रेटिंग अनिवार्य कर दी गई और रेटेड एनबीएफसी के लिए पूरे क्षेत्र में सार्वजनिक जमा स्वीकार करने की सीमा को सुसंगत बनाया गया। इसके अलावा, एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी (जमाराशि स्वीकार करने वाले) के लिए, न्यूनतम टियर-1 पूंजी आवश्यकता को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया और साथ ही एनबीएफसी-डी और एनडीएसआई के आस्ति वर्गीकरण मानदंडों को बैंकों के अनुरूप बनाया गया (आरबीआई, 2014)।

सबसे हालिया बदलाव स्केल-आधारित विनियमन (एसबीआर) के रूप में हुआ, जो 1 अक्तूबर, 2022 से प्रभावी हुआ। इस क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के साथ-साथ बढ़ते अंतर्संबंध और एनबीएफसी के बदलते जोखिम प्रोफाइल के कारण यह जरूरी हो गया था। इस नए नियामकीय ढांचे के तहत, एनबीएफसी को आकार, गतिविधि या कथित जोखिम के आधार पर चार लेयरों (टॉप, अपर, मिडिल और बेस) में से किसी में रखा जाता है। वर्तमान में, टॉप लेयर को खाली रखा गया है, और यदि आवश्यकता हुई तो रिज़र्व बैंक सघन जांच के लिए एनबीएफसी को अपर लेयर से टॉप लेयर में स्थानांतरित कर सकता है। एसबीआर विनियमन के लिए एक संकर दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है, जो विवेकपूर्ण और सदाचार विनियमन के स्तंभों के तहत इकाई और गतिविधि-आधारित विनियमन दृष्टिकोणों को जोड़ता है। यह दृष्टिकोण लगातार विकसित हो रहे एनबीएफसी क्षेत्र के लिए उनकी गतिशीलता को बाधित किए बिना तैयार किया गया है।

एनबीएफसी क्षेत्र के भीतर विविध व्यावसायिक मॉडलों को देखते हुए, एसबीआर नियामकीय तीव्रता में लेयर-वार प्रगतिशील वृद्धि की परिकल्पना करता है। एक ओर बैंकों और अपर लेयर वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-यूएल) के बीच और दूसरी ओर विभिन्न लेयरों वाली एनबीएफसी के बीच पूंजी, विवेकपूर्ण और अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के प्रमुख क्षेत्रों में विनियमन के सामंजस्य की सीमा सारणी 3 में प्रस्तुत की गई है। एसबीआर अन्य लेयरों की तुलना में एनबीएफसी-यूएल के लिए उन्नत नियामकीय जांच करता है, किन्तु बैंकों के समान नहीं। इस तरह, एसबीआर विनियमन के लिए समायोजन दृष्टिकोण को संरक्षित करता है जहां भारतीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रतिभागियों के अलग-अलग व्यावसायिक मॉडल और क्षमता को बनाए रखा जाता है, जबकि यह सुनिश्चित किया जाता है कि वित्तीय स्थिरता से समझौता न हो।

बैंकों और एनबीएफसी के बीच अंतर का एक प्रमुख क्षेत्र सार्वजनिक जमा स्वीकार करने की अनुमति है, जो केवल मुट्ठी भर एनबीएफसी के लिए उपलब्ध है[4]। 1997 से, नए एनबीएफसी को सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के लिए पंजीकरण का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। वास्तव में, विनियामकीय दृष्टिकोण एनबीएफसी की जमा-प्राप्ति गतिविधियों को हतोत्साहित कर रहा है। यह रिज़र्व बैंक को क्रमशः एनबीएफसी के व्यवसाय को शुरू करने या बंद करने के लिए कम प्रवेश और निकास बाधाओं को बनाए रखने और उनके संबंधित व्यावसायिक डोमेन में नवाचार और विशेषज्ञता की सुविधा प्रदान करने की अनुमति देता है (राव, 2024)।

बेस लेयर वाले एनबीएफसी अपने छोटे आकार और सीमित अंतर्संबंधों के कारण मिडिल और अपर लेयरों की तुलना में कम कठोर विनियमन के अधीन हैं। नतीजतन, इस आलेख में विश्लेषण केवल एनबीएफसी-यूएल और एमएल तक ही सीमित रखा है। एनबीएफसी क्षेत्र[5] में एनबीएफसी-यूएल, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें मार्च 2023 के अंत में अपर लेयर वाली नौ एनबीएफसी की आस्तियां कुल आस्तियों का लगभग पांचवां हिस्सा रहा है। (चार्ट 4)।

[3] कार्य समूह (अध्यक्ष: श्रीमती उषा थोरात) और लघु व्यवसायों और निम्न आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर समिति (अध्यक्ष: डॉ. नचिकेत मोर)।

[4] सितंबर 2023 के अंत तक 26 एनबीएफसी।

[5] विश्लेषण के उद्देश्य से यहाँ एनबीएफसी क्षेत्र में केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल शामिल हैं, जिसमें स्टैंड-अलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी), मूल निवेश कंपनियाँ (सीआईसी) और आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) शामिल नहीं हैं। दो एनबीएफसी-आईसीसी (एनबीएफसी-यूएल सहित) के एक सीआईसी में विलय के मद्देनजर, संबंधित कंपनियों को दिसंबर 2023 के अंत में नमूने में शामिल नहीं किया गया है।

सारणी 3: बैंकों और एनबीएफसी की महत्वपूर्ण नियामकीय विशेषताएं

मौजूदा विनियामकीय आवश्यकताएं	एनबीएफसी			बैंक	टिप्पणी
	बेस लेयर	मिडिल लेयर	अपर लेयर		
पूंजीगत दिशानिर्देश					
न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी	✓	✓	✓	✓*	एक सार्वभौमिक बैंक के लिए यह 1,000 करोड़ रुपये है, जबकि एनबीएफसी के लिए यह 10 करोड़ रुपये है (चरणबद्ध तरीके से 31 मार्च 2027 तक हासिल किया जाना है)।
जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात	–	✓	✓*	✓**	एक सार्वभौमिक बैंक की पूँजी आवश्यकता में ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम पूँजी शुल्क शामिल हैं। एनबीएफसी के लिए, यह केवल ऋण जोखिम पूँजी शुल्क पर आधारित है। एनबीएफसी-यूएल को 15 प्रतिशत की समग्र पूँजी आवश्यकता के भीतर जोखिम भारित आस्तियों के न्यूनतम नौ प्रतिशत की सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। बेस लेयर में गोल्ड लोन एनबीएफसी को न्यूनतम 12 प्रतिशत की टियर 1 पूंजी बनाए रखनी होगी।
मानक आस्ति प्रावधान	✓	✓*	✓**	✓**	बैंकों की तरह, एनबीएफसी-यूएल को भी मानक आस्तियों के लिए विभेदक प्रावधान बनाए रखना होगा।
आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी)	–	✓	✓	✓*	एनबीएफसी के लिए आईसीएएपी उसी प्रकार होगा जैसा कि बेसल III मानदंडों के पिलर 2 के अंतर्गत बैंकों के लिए निर्धारित किया गया है।
विवेकपूर्ण दिशानिर्देश					
ऋण / निवेश का संकेन्द्रण	–	✓	✓*	✓**	बैंकों के समान, एनबीएफसी-यूएल@ पर भी बड़ी जोखिम संरचना लागू है, हालांकि बैंकों के लिए अधिक विस्तृत संरचना है।
आंतरिक जोखिम सीमाएँ	–	✓	✓	✓*	संवेदनशील क्षेत्र में निवेश की आंतरिक सीमाओं के अलावा, एनबीएफसी-यूएल को अन्य महत्वपूर्ण (एनबीएफसी सहित) क्षेत्र में भी निवेश की आंतरिक सीमाएं रखनी चाहिए। बैंकों के लिए अधिक विस्तृत विनियमन।
अभिशासन और प्रकटीकरण दिशानिर्देश					
प्रकटीकरण विनियमन	✓	✓*	✓***	✓**	बैंकों और एनबीएफसी-यूएल को सूचीबद्ध कंपनी की तरह ही प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। हालांकि, एनबीएफसी-यूएल को वास्तविक लिस्टिंग से पहले भी इन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
लिस्टिंग	–	–	✓*	✓	एक नए सार्वभौमिक बैंक को परिचालन शुरू होने के बाद छह साल के भीतर सूचीबद्ध होना होगा, जबकि एक एनबीएफसी को एनबीएफसी-यूएल के रूप में पहचान के बाद सूचीबद्ध होने के लिए तीन साल का समय मिलता है।
कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) / कोर वित्तीय सेवा समाधान (सीएफएसएस)	–	✓	✓	✓	10 या अधिक शाखाओं वाली एनबीएफसी को सीएफएसएस अपनाना होगा।
अन्य					
प्रासंगिक अधिनियमों के तहत अनुमत गतिविधियाँ	–	–	–	✓	बैंक केवल उन्हीं गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जिनका बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत विशेष प्रावधान है। एनबीएफसी को नियंत्रित करने वाले आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
वाणिज्यिक विस्तार	–	–	–	✓	एनबीएफसी (स्वर्ण ऋण एनबीएफसी को छोड़कर) के परिचालन पर लगभग कोई विनियामक प्रतिबंध नहीं है, जबकि बैंकों के लिए विस्तृत नीति मौजूद है।
प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल)	–	–	–	✓	समायोजित निवल बैंक ऋण का न्यूनतम 40% पीएसएल के लिए होना चाहिए और एसएफबी के लिए यह 75 प्रतिशत है। एनबीएफसी के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।
आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) वित्तपोषन की अधिकतम सीमा	✓	✓	✓	✓*	बैंकों और एनबीएफसी दोनों के लिए आईपीओ हेतु वित्तीय अभिदान की अधिकतम सीमा।

नोट: 1. – लागू नहीं; ✓ लागू; ✓* लागू और कठोर; ✓** लागू और अधकि कठोर

2. ^ एनबीएफसी-पी2पी, एनबीएफसी-एए और सार्वजनिक निधियों का लाभ नहीं उठाने वाली और कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं रखने वाली एनबीएफसी के लिए एनओएफ ₹2 करोड़ है। एनबीएफसी-आईएफसी और आईडीएफएनबीएफसी के लिए एनओएफ ₹300 करोड़ है।

एसपीडी को छोड़कर जहां बाजार जोखमि पूंजी लागू होती है।

@ एनबीएफसी-आईएफसी पर थोड़ी अधकि सीमा लागू होती है।

स्रोत: आरबीआई, 2021ए; आरबीआई, 2021बी और राव, 2024।

चार्ट 4: एनबीएफसी का लेयर-वार वितरण
(मार्च 2023 के अंत में प्रतिशत में हिस्सेदारी)

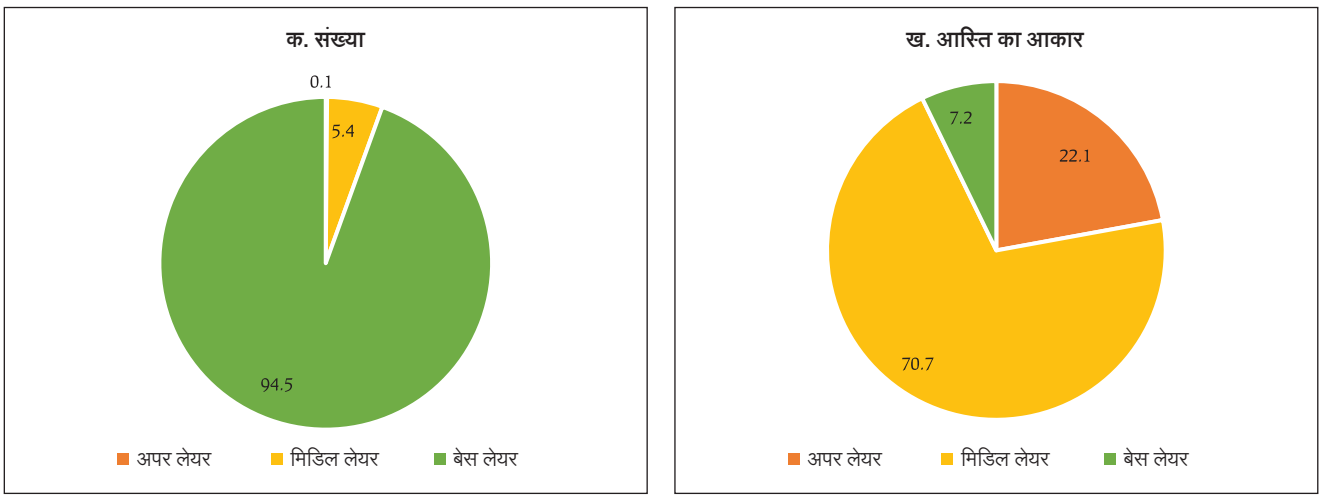

नोट: टॉप लेयर अभी रिक्त है।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

IV. एनबीएफसी क्षेत्र का प्रदर्शन

ए. तुलन पत्र

एनबीएफसी क्षेत्र ने 2023 के दौरान निरंतर वृद्धि प्रदर्शित करना जारी रखा, जो मुख्य रूप से ऋण वृद्धि द्वारा संचालित था, भले ही निवेश में गिरावट आई हो। देयताओं के मामले में, एनबीएफसी द्वारा उधार पिछले वर्ष की तुलना में कम दर से बढ़ा (सारणी 4)।

आस्तियां

उपभोक्ता ऋण के कुछ घटकों में उच्च वृद्धि के बारे में कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2023 में एनबीएफसी द्वारा खुदरा ऋणों की चुनिंदा श्रेणियों पर जोखिम भार बढ़ा दिया। इन उपायों के बाद अप्रतिभूत ऋणों में वृद्धि कम हो गई है (चार्ट 5)।

सारणी 4: एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़)

	वर्ष के अंत में बकाया राशि			वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में)	
	दिसं -22	मार्च-23	दिसं-23	22 दिसं से 21 दिसं तक	23 दिसं से 22 दिसं तक
1. शेयर पूंजी	1,14,533	1,19,432	1,29,479	11.6	13.0
2. आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	7,97,827	8,58,744	8,79,323	20.8	10.2
3. सार्वजनिक जमा	1,15,850	89,322	1,06,405	22.5	-8.2
4. कुल उधार	27,67,612	29,43,224	30,72,171	16.3	11.0
5. अन्य देयताएं	2,91,141	3,29,415	3,25,561	7.1	11.8
कुल देयताएँ / आस्तियां	**40,86,963**	**43,40,138**	**45,12,938**	**16.4**	**10.4**
1. ऋण और अग्रिम	31,42,244	33,65,863	35,88,631	16.4	14.2
2. निवेश	5,25,669	5,38,714	4,98,172	19.7	-5.2
3. नकदी एवं बैंक शेष	1,61,094	1,70,274	1,57,821	6.7	-2.0
4. अन्य आस्तियां	2,57,956	2,65,287	2,68,315	17.0	4.0

नोट: 1. डेटा अनंतिम है और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित है।
2. आकड़े मेल नहीं खा सकते हैं; क्योंकि सभी घटकों की रिपोर्ट यहाँ नहीं की गई है।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

चार्ट 5: एनबीएफसी द्वारा ऋण और अग्रिम

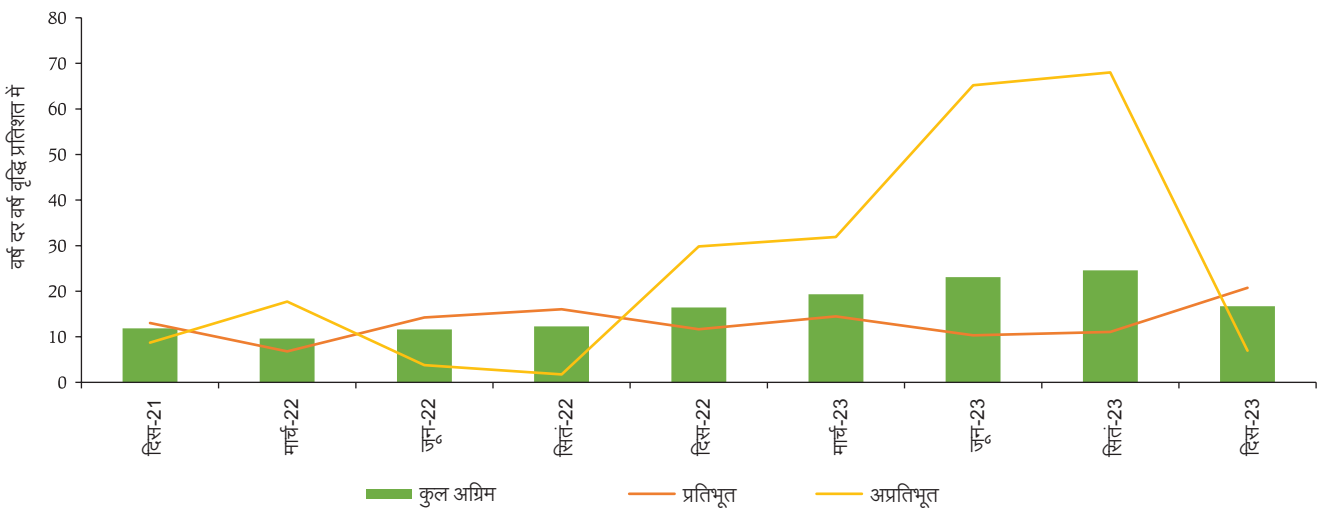

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

एनबीएफसी के ऋण में अप्रतिभूत ऋण लगभग 26 प्रतिशत है, जबकि मिडिल लेयर की ऋण पोर्टफोलियो में इसकी हिस्सेदारी अधिक है (चार्ट 6ए)। सभी एनबीएफसी लेयरों पर अप्रतिभूत ऋणों में शुरुआती तेज वृद्धि और उसके बाद आई मंदी मिडिल लेयर की एनबीएफसी द्वारा संचालित थी। अपर लेयर की एनबीएफसी द्वारा अप्रतिभूत ऋणों में विस्तार की गति भी धीमी हो गई है, हालांकि यह दोहरे अंकों में बनी हुई है (चार्ट 6बी)।

एनबीएफसी क्रेडिट का 70 प्रतिशत से अधिक उद्योग और खुदरा क्षेत्रों को जाता है, जिसमें दिसंबर 2023 के अंत में उद्योग का लगभग दो-पांचवां हिस्सा रहा है, जो इसे एनबीएफसी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनाता है (चार्ट 7 ए)। 2023 में, उद्योग, सेवाओं और खुदरा ऋणों के लिए ऋण दोहरे अंकों में बढ़ा, जबकि कृषि और संबद्ध गतिविधियों में आधार प्रभाव के कारण कमी आई (चार्ट 7 बी)। खुदरा क्षेत्र को ऋण वाहनों, उपभोक्ता टिकाऊ

चार्ट 6: लेयर-वार अप्रतिभूत ऋणों में रुझान

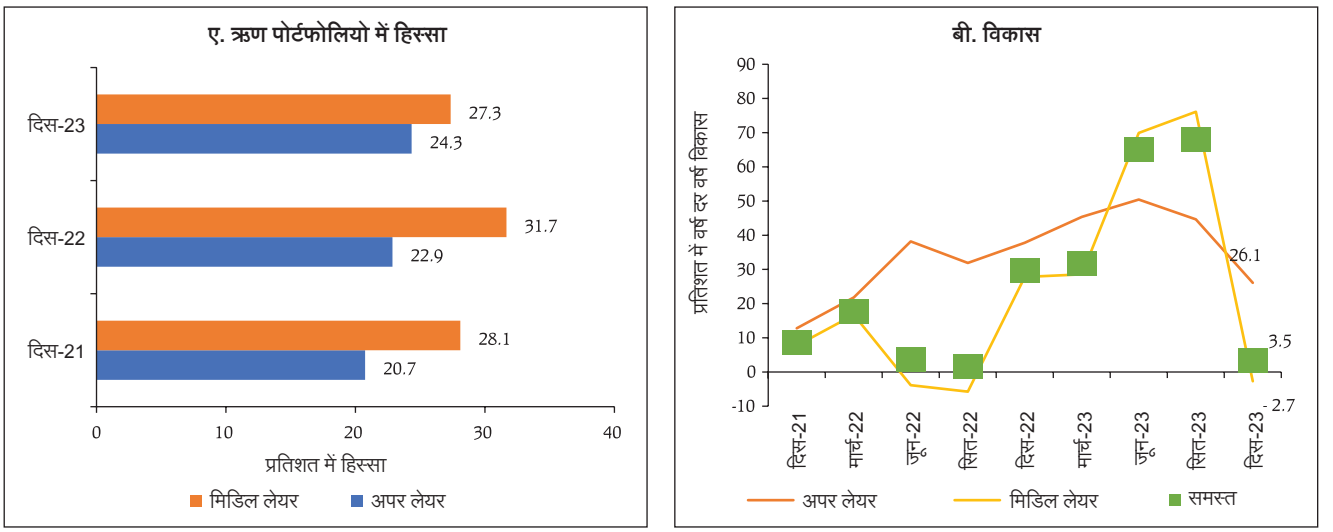

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

चार्ट 7: एनबीएफसी ऋण का क्षेत्रकवार वितरण

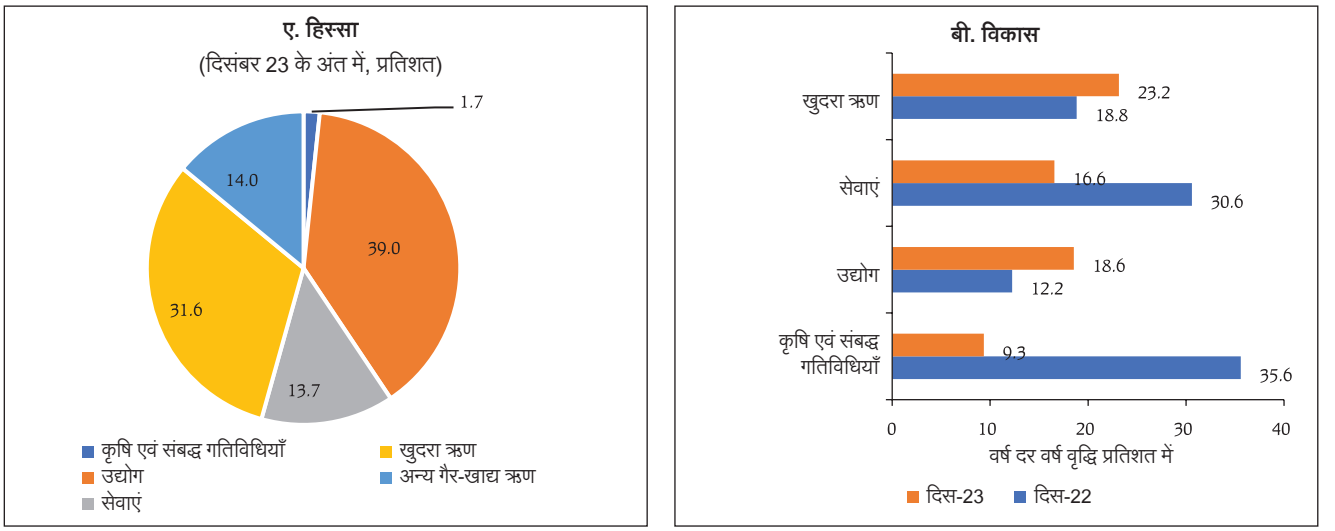

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

वस्तुओं, स्वर्ण ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के क्षेत्रों के लिए उधार में मजबूत वृद्धि के कारण संचालित किया गया था।

लेयर-वार और स्वामित्व-वार विश्लेषण से इस क्षेत्र की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। एनबीएफसी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता उद्योग है, जो बड़े सरकारी स्वामित्व वाली[6] एनबीएफसी की उपस्थिति से लाभान्वित होता है जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण देते हैं। अपर लेयर में सभी एनबीएफसी निजी स्वामित्व वाली हैं और मुख्य रूप से खुदरा क्षेत्र की ऋण मांगों को पूरा करती हैं (चार्ट 8)।

देयताएं

एनबीएफसी अपनी निधीयन जरूरतों के लिए बाजारों और बैंकों दोनों से उधारी पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं (आरबीआई, 2023)। एनबीएफसी-यूएल, अपनी मजबूत तुलन पत्र और बाजार स्थिति के कारण प्रतिभूत उधारी पर अधिक निर्भर करती हैं।

चार्ट 8: एनबीएफसी क्षेत्र का क्षेत्रकवार ऋण पोर्टफोलियो
(दिसंबर 2023 के अंत में)

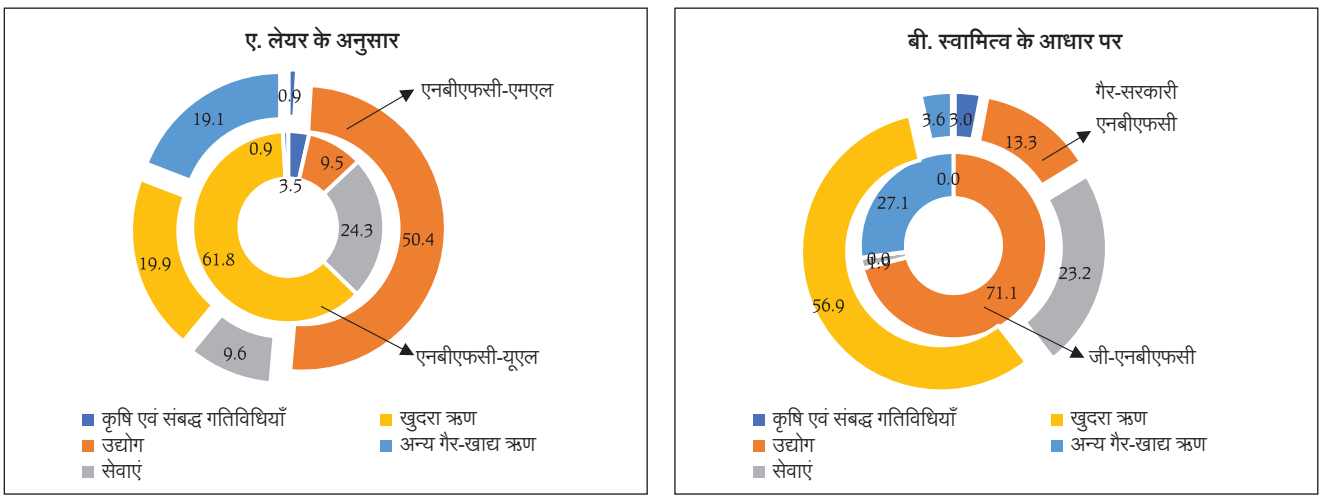

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

[6] सरकारी एनबीएफसी को डिजाइन के अनुसार या तो मिडिल लेयर या बेस लेयर पर रखा जाता है। यह आलेख केवल मिडिल लेयर की सरकारी एनबीएफसी पर विचार करता है।

चार्ट 9: एनबीएफसी का उधार प्रोफ़ाइल

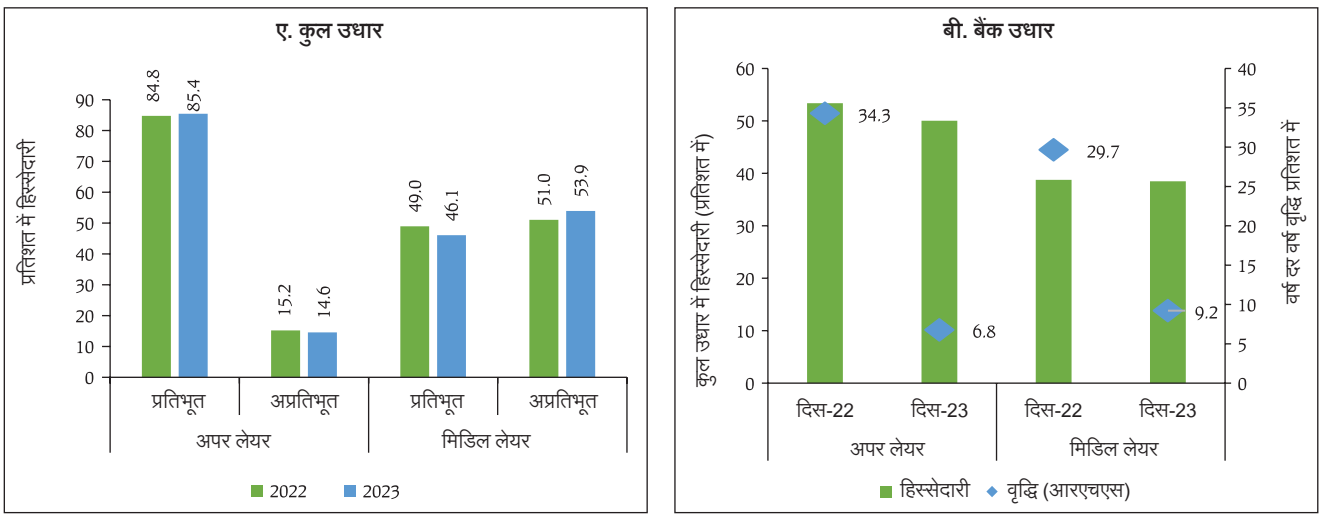

नोट: 1. आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
2. बैंक उधार में प्रत्यक्ष उधार के साथ-साथ बाजार साधनों के माध्यम से उधार लेना भी शामिल है।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

दूसरी ओर, एनबीएफसी-एमएल संभवतः उच्च दरों पर अप्रतिभूत उधारी पर अधिक निर्भर करती हैं (चार्ट 9 ए)। बैंक एनबीएफसी के लिए निधि का प्रमुख स्रोत बने हुए हैं, न केवल प्रत्यक्ष उधार के माध्यम से, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र की सदस्यता के माध्यम से भी। एनबीएफसी को अपने निधि जुटाने के आधार को व्यापक बनाने और बैंकों पर निर्भरता को सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास में, रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2023 में एनबीएफसी को बैंक ऋण पर जोखिम भार बढ़ा दिया था।

बी. एनबीएफसी क्षेत्र का वित्तीय प्रदर्शन और विवेकपूर्ण संकेतक

लाभप्रदता संकेतकों, अर्थात आस्तियों पर आय (आरओए) और इक्विटी पर आय (आरओई) [चार्ट 10] के अनुसार, इस क्षेत्र की आधार रेखा में लगातार सुधार हुआ है। एनबीएफसी-

चार्ट 10: एनबीएफसी क्षेत्र की लाभप्रदता

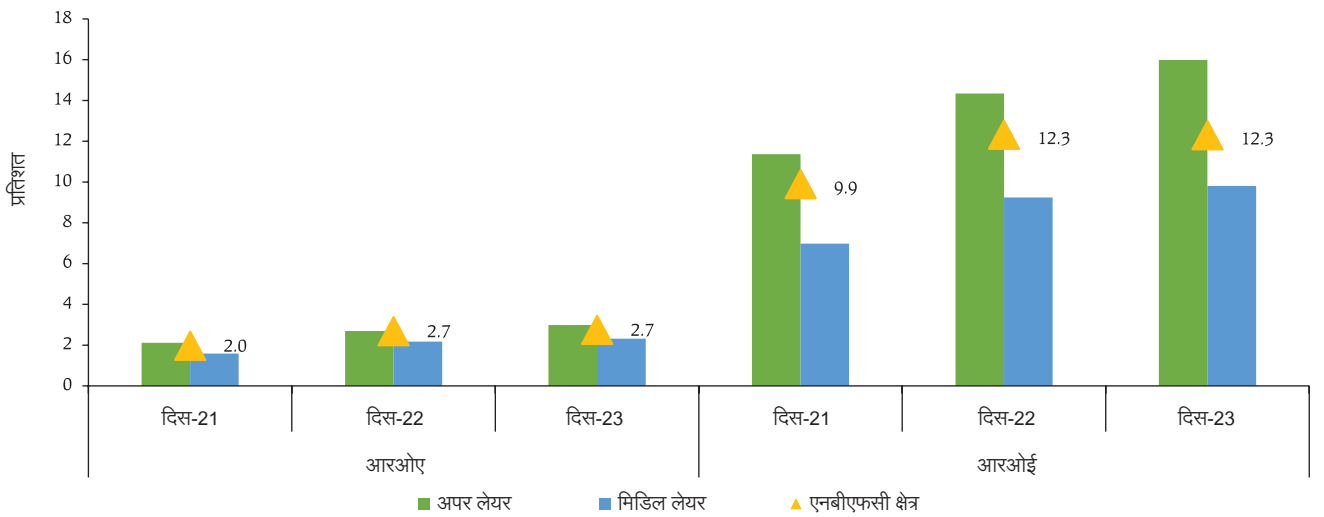

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

चार्ट 11: आस्ति गुणवत्ता

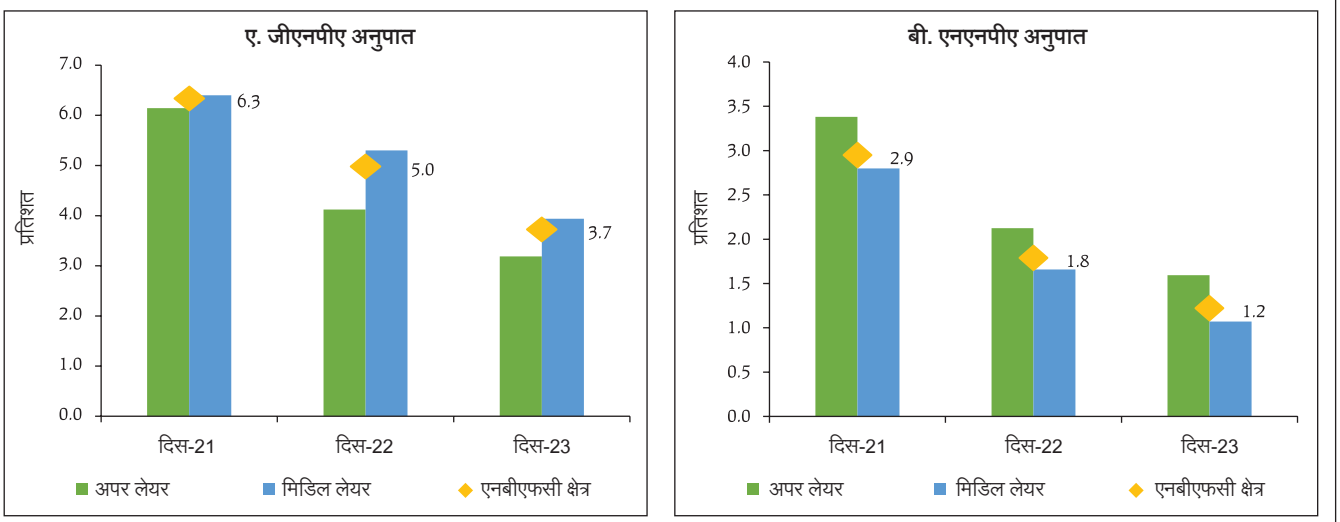

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

यूएल ने लाभप्रदता के संबंध में एनबीएफसी-एमएल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसका मुख्य कारण अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के बदले कम प्रावधान और कम ब्याज व्यय रहा है।

इस क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। अपर लेयर में यद्यपि एनबीएफसी का सकल एनपीए (जीएनपीए) अनुपात मिडिल लेयर की तुलना में कम है, तथापि मिडिल लेयर ने अपने जोखिम युक्त ऋण पोर्टफोलियो के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए रखा, जिससे उनका निवल एनपीए (एनएनपीए) अनुपात एनबीएफसी-यूएल (चार्ट 11) से नीचे आ गया।

जीएनपीए अनुपात में गिरावट सभी क्षेत्रों में देखी गई है, खुदरा ऋण खंड में अप्रतिभूत खुदरा उधार के बावजूद सबसे कम जीएनपीए अनुपात है (चार्ट 12ए)। खुदरा ऋणों

चार्ट 12: आस्ति गुणवत्ता, क्षेत्रकवार

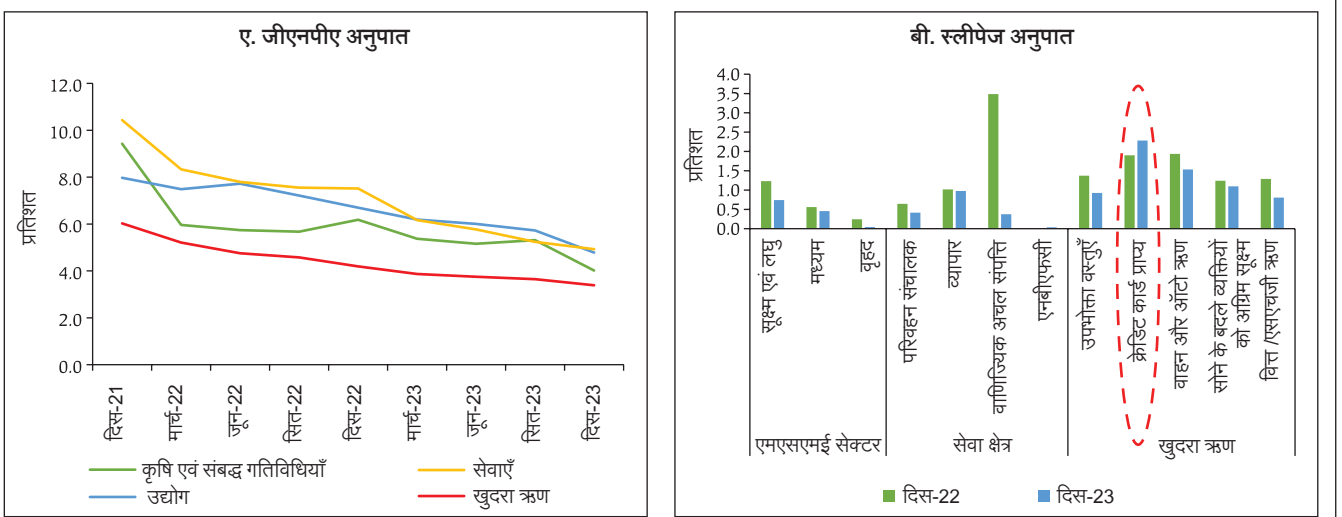

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

7 स्लिपेज अनुपात से तात्पर्य तिमाही के दौरान कुल बकाया अग्रिमों में अनर्जक आस्तियों में वृद्धि के अनुपात से है।

चार्ट 13: स्वामित्व के आधार पर आस्ति गुणवत्ता (जीएनपीए अनुपात)

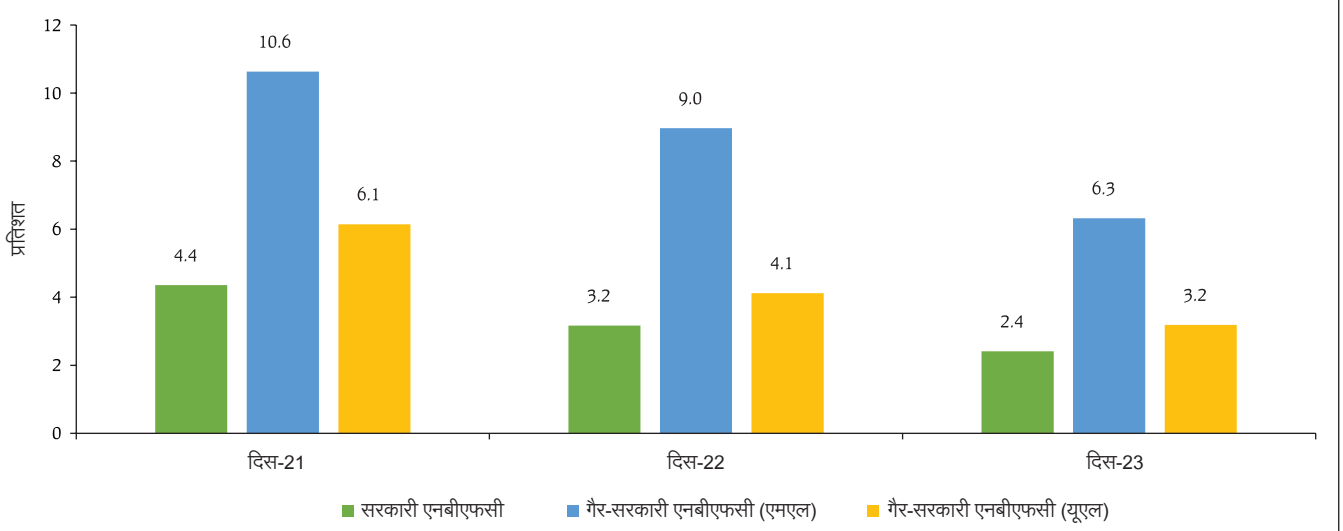

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई

की महत्वपूर्ण श्रेणियों जैसे कि वाहन ऋण और स्वर्ण ऋण में स्लीपेज अनुपात[7] अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहा है, हालांकि क्रेडिट कार्ड प्राप्य खंड को छोड़कर दिसंबर 2023 के अंत में इसमें कमी आई है (चार्ट 12बी)।

सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी का अपेक्षाकृत कम एनपीए अनुपात है (चार्ट 13)। जैसा कि पहले बताया गया है, गैर-सरकारी एनबीएफसी, विशेष रूप से मिडिल लेयर वाले वाले, खुदरा ऋण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां हाल के दिनों में स्लीपेज बढ़ गई है।

खुदरा ऋणों की कुछ श्रेणियों पर जोखिम भार में वृद्धि के साथ, गैर-प्रतिभूत ऋणों के बड़े पोर्टफोलियो वाले एनबीएफसी को विनियामकीय पूंजी अपेक्षाओं का पालन करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, समग्र रूप से क्षेत्र, एनबीएफसी-यूएल और

चार्ट 14: पूंजी पर्याप्तता

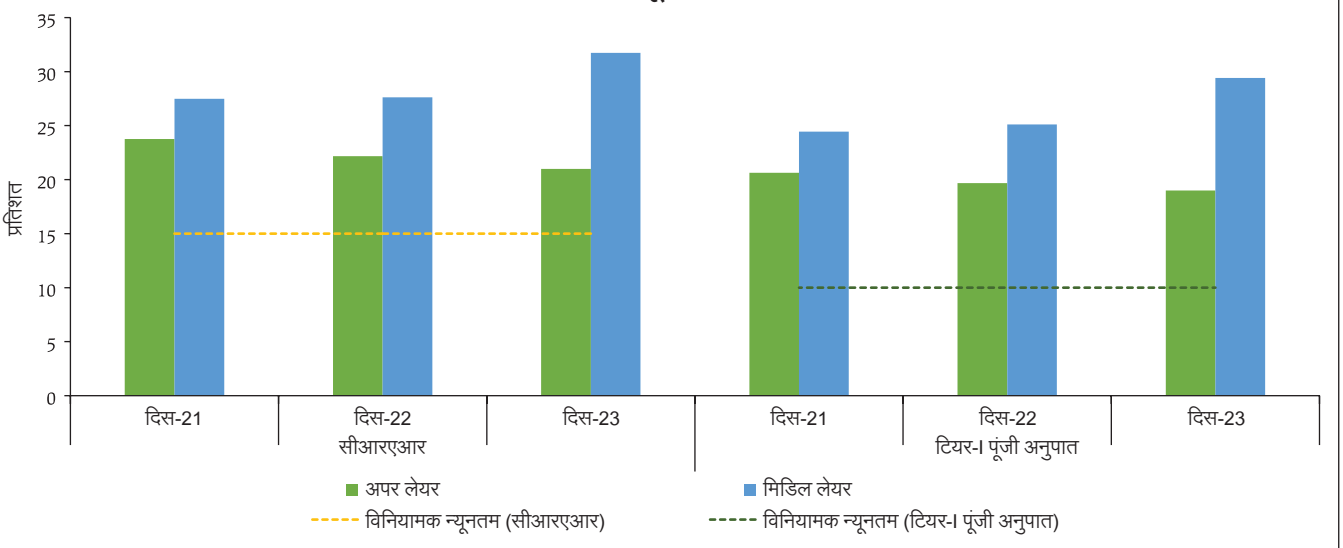

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और केवल एनबीएफसी-यूएल और एनबीएफसी-एमएल से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणी, आरबीआई।

एनबीएफसी-एमएल दोनों, अच्छी तरह से पूंजीकृत बने हुए हैं, जो उच्च आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी वित्तीय सुदृढ़ता को दर्शाता है (चार्ट 14)।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत, पूंजी और आस्ति गुणवत्ता एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति की निगरानी के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं, और यह 1 अक्तूबर, 2024 से सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी के लिए लागू हो जाएगा। दिसंबर 2023 के अंत में पर्याप्त पूंजी और कम एनएनपीए के साथ, ये एनबीएफसी आरामदायक स्थिति में हैं। पीसीए ढांचा 1 अक्तूबर, 2022 से अन्य एनबीएफसी के लिए पहले से ही प्रभावी है।

निष्कर्ष

वैश्विक स्तर पर, एनबीएफआई वास्तविक अर्थव्यवस्था को वित्तपोषित करने और आर्थिक विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न देश एनबीएफआई के लिए ऐसे नियम लागू करते हैं जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हों। भारत की तुलना में, उन्नत देशों में गैर-बैंक आकार में बहुत बड़े हैं और जटिल बाजार परिवेश में काम करते हैं।

भारत में एनबीएफसी क्षेत्र एसबीआर ढांचे के अंतर्गत सुदृढ़ बना हुआ है। दिसंबर 2023 के अंत में, इस क्षेत्र ने ऋण, पर्याप्त पूंजी और कम चूक अनुपात में दोहरे अंकों की वृद्धि प्रदर्शित करना जारी रखा। सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को पीसीए मानदंडों के विस्तार के हालिया नियामकीय उपाय से इस क्षेत्र को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। एनबीएफसी को बैंक ऋण पर जोखिम भार में हाल ही में हुई वृद्धि के प्रतिक्रिया स्वरूप, उन्होंने अपने वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाना शुरू कर दिया है और बैंकों से उधार लेने पर अत्यधिक निर्भरता कम कर दी है। उद्योग और सेवा क्षेत्र के ऋणों के साथ-साथ स्वर्ण ऋण, वाहन और आवास ऋण जैसे प्रतिभूत खुदरा ऋण में मजबूत वृद्धि जारी है।

आगे बढ़ते हुए, एनबीएफसी को तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य और उभरते जोखिमों और चुनौतियों, विशेष रूप से साइबर-सुरक्षा और जलवायु जोखिम के क्षेत्रों में, के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और आंतरिक लेखा परीक्षा जैसे आश्वासन कार्य, वित्तीय इकाई और समग्र वित्तीय प्रणाली दोनों की मजबूती और सुदृढ़ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (जे, स्वामीनाथन, 2024)। भारतीय वित्तीय प्रणाली में उनकी बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी पर यह दायित्व है कि वे जोखिमों की पहचान करें और उनका प्रबंधन करें और अपने आश्वासन कार्यों को मजबूत करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एनबीएफसी क्षेत्र एक सतत विकास पथ बना रहे।

संदर्भ

Ehrentraud, J., Mure, S., Noble, E., & Zamil, R. (2024). Safeguarding the financial system's spare tyre: regulating non-bank retail lenders in the digital era. *FSI Insights on policy implementation No 56.* Bank for International Settlements.

FSB. (2023a). *Enhancing the Resilience of Non-Bank Financial Intermediation- Progress report.*

FSB. (2023b). Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation.

J, Swaminathan. (2024). Shared Vision, Shared Responsibilities: Advancing Assurance in Banking Supervision. *Speech by Shri Swaminathan J, Deputy Governor, Reserve Bank of India.*

Rao, M. R. (2024). No More a Shadow (of a) Bank. *Remarks delivered by Shri M. Rajeshwar Rao, Deputy Governor, Reserve Bank of India.*

RBI. (2014). *Revised Regulatory Framework for NBFC.* Retrieved from https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=9327 .

RBI. (2023). *Report on Trend and Progress of Banking in India, 2022-23*

RBI. (2021a). Scale Based Regulation (SBR): A Revised Regulatory Framework for NBFCs.

RBI. (2021b). *Discussion Paper on Revised Regulatory Framework for NBFCs- A Scale Based Approach.*